Title: Need to take concrete steps for effective implementation of poverty alleviation programmes in the country-Laid.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद)**:** अध्यक्ष महोदय, सरकारी दावे के अनुसार अभी 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं और उनके जीवन को सुधारने के लिए सरकार गत् अनेक वर्ो से विभिन्न योजनाओं के तहत 350 अरब रूपया प्रति र्वा खर्च करती आ रही है। यदि यह राशि प्रत्येक गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले को सीधे दे दी जाये तो वह प्रतिदिन तीन किलो गेहूं 7.50 रूपया प्रति किलो के हिसाब से खरीद सकता है और इस प्रकार उसकी भूख की समस्या समाप्त हो सकती है। परंतु देखा जा रहा है कि सरकार धन भी खर्च कर रही है और दूसरी ओर गरीबी भी बढ़ रही है। देश में 1983 से 1993 तक रोजगार के अवसर प्रतिर्वा 2 प्रतिशत के हिसाब से बढ़े हैं, किंतु 1993 से 2000 के बीच यह प्रतिशत मात्र एक प्रतिशत रह गया और इसके कारण पहले जो देश में वार्षिक बेरोजगारी 6.03 प्रतिशत बढ़ती थी अब इन अंतिम वर्ो में 7.32 प्रतिशत बढ़ी है। गरीबी उन्मूलन में सबसे बड़ी बाधा योजना क्रियान्वयन में भ्रटाचार और योजनाओं के लिए आबंटित धन को अन्य मदों में व्यय करना है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि वह विकास की योजनाओं में विशेाकर गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यापक सुधार के लिए अविलम्ब कारगार कदम उठाये ताकि परिणाम धरातल पर दिखायी दें।